भारत सरकार

सहकारिता मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1788

04 अगस्त, 2021 को उत्तरार्थ

विषय: कृषि क्षेत्र में सहकारिता गतिविधियों को बढ़ाया जाना

1788. श्री अजय प्रताप सिंह:

क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा सहकारिता गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई योजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ख) क्या सरकार कृषि क्षेत्र में सहकारिता गतिविधियों को बढ़ाने के लिए कोई विशेष योजना लागू करने की योजना बना रही है?

उत्तर

सहकारिता राज्य मंत्री (श्री बी.एल.वर्मा)

(क) विभिन्न कृषि और संबद्ध गतिविधियों को करने वाली सहकारी समितियों को बढ़ावा देने, विकसित करने और वित्तपोषण के लिए राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एनसीडीसी) के माध्यम से, कृषि सहकारिता योजना पर केंद्रीय क्षेत्र एकीकृत योजना (सीएसआईएसएसी) के तहत सहायता प्रदान की जाती है। इनमें, अन्य बातों के साथ-साथ, कृषि आदानों की आपूर्ति के अलावा, कृषि उपज का विपणन, भंडारण और प्रसंस्करण शामिल हैं। सहकारी समितियों को सावधि ऋण के अलावा राज्य की श्रेणी के आधार पर 15% से 25% तक की सब्सिडी प्रदान की जाती है। सरकार भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ (नेफेड) के खरीद कार्यों के लिए गारंटी भी प्रदान करती है।

सीएसआईएसएसी योजना के तहत, ऐसे किसानों को भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ (एनसीयूआई) और राष्ट्रीय सहकारी प्रशिक्षण परिषद (एनसीसीटी) के माध्यम से प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए सहायता प्रदान की जाती है जो विभिन्न प्रकार की सहकारी समितियों के सदस्य और कर्मचारी हैं।

किसानों को उनकी उपज का लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के लिए, सरकार "प्रधान मंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान" (पीएम-आशा) का कार्यान्वयन कर रही है। इस योजना के तहत, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग (डीएएंडएफडब्ल्यू) दलहन, तिलहन और खोपरा की खरीद के लिए मूल्य समर्थन योजना (पीएसएस) क्रियान्वित करता है। तिलहनों के लिए, डीएएंडएफडब्ल्यू भावांतर भुगतान योजना (पीडीपीएस) भी लागू करता है।

कृषि अवसंरचना कोष (एआईएफ) के तहत, फस्लोपरांत प्रबंधन अवसंरचना और सामुदायिक खेती परिसंपत्ति के निर्माण के लिए अन्य के अलावा, प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों (पीएसीएस), सहकारी समितियों के संघ, एफपीओ, विपणन सहकारी समितियों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

(ख) सरकार एआईएफ योजना के माध्यम से देश में कृषि अवसंरचना की स्थापना में सहकारी समितियों, विशेष रूप से पीएसीएस के योगदान को बढ़ाने पर जोर दे रही है।

******